भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4403

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पुनर्गठन

†4403. श्री अरुण भारतीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 25 शहरों में प्रायोगिक परियोजनाओं के आधार पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) को पुनर्गठित करने का विचार है और यदि हां, तो इन प्रायोगिक पहलों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) पुनर्गठित एनयूएलएम के आरंभ करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है तथा उक्त मिशन के अंतर्गत, विशेषकर बिहार में, किन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा;

(ग) पुनर्गठित मिशन के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित शहरी गरीब परिवारों की कुल संख्या क्या है साथ ही उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए क्या रणनीति बनाई गई है;

(घ) पुनर्गठित एनयूएलएम के कार्यान्वयन में कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता संवर्धन के लिए क्या भूमिका परिकल्पित की गई है; और

(ङ) मिशन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों का प्रस्ताव किया गया है ?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2014 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) लागू किया और 30 सितंबर, 2024 को यह मिशन समाप्त हो गया।

इसके अलावा, 1 अक्टूबर, 2024 से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पटना सहित 25 चयनित शहरों में शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु 3 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की, जिसे बाद में 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया। प्रायोगिक परियोजना में

शहरी गरीबों को आजीविका प्रदान करने और 6 कमजोर समूहों यानी गिग श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, अपशिष्ट संबंधी कार्य करने वाले श्रमिकों, देखभाल कार्य करने वाले श्रमिकों और घरेलू श्रमिकों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हे सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

बजट 2025-26 के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 'हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमज़ोर समूहों की सहायता को प्राथमिकता दे रही है। शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से उनकी आय में सुधार, स्थायी आजीविका और बेहतर जीवन स्तर के लिए एक योजना लागू की जाएगी'।

*****